



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270055
CG-DL-E-11022026-270055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 665]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

का.आ. 699(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 891 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2015 संशोधन करती है, सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे संशोधन से पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, “मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग में प्रादेशिक निदेशिक” शब्दों के स्थान पर “अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और नई दिल्ली में प्रादेशिक निदेशिक” शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 16 फरवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. नीति-01/4/2025-सीएल-V-एमसीए]

बालामुरुगन देवराज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2026

S.O. 699(E).— In exercise of the powers conferred by section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs number S.O. 891 (E), dated 31st March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st March, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, namely:-

In the said notification, for the words “Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, Noida, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong”, the words “Regional Directors at Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Navi Mumbai and New Delhi” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 16th day of February, 2026.

[F. No. Policy-01/4/2025-CL-V-MCA]
BALAMURUGAN DEVARAJ, Jt. Secy.